सबसे ख़तरनाक -पाश

पाश-क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश की एक-एक कविता सत्ता और व्यवस्था से संघर्ष का जिंदा दस्तावेज़ है। वे शहीद भगत सिंह की परंपरा के सिपाही थे। इसे भी संयोग ही कहिये कि दोनों 23 मार्च के दिन ही शहीद हुए। भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार ने फ़ासी पर लटकाया और पाश को धर्मांध खालिस्तानी आतंकवादियों ने गोलियों से भूंन डाला।

मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती
पुलिस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती
ग़द्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे
ख़तरनाक नहीं होती
बैठे-बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है
सहमी-सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है
सबसे ख़तरनाक नहीं होता
कपट के शोर में सही होते हुए भी
दब जाना बुरा तो है
जुगनुओं की लौ में पढना
मुट्ठियां भींचकर बस वक्त
निकाल लेना बुरा तो है
सबसे ख़तरनाक नहीं होता
सबसे ख़तरनाक होता है
मुर्दा शांति से भर जाना
तड़प का न होना/सब कुछ
सहन कर जाना
घर से निकलना काम पर
और काम से लौटकर घर आना
सबसे ख़तरनाक होता है
हमारे सपनों का मर जाना
सबसे ख़तरनाक वो घड़ी होती है
आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो
आपकी नज़र में रूकी होती है
सबसे ख़तरनाक वो आंख होती है
जिसकी नज़र दुनिया को
मोहब्बत से चूमना भूल जाती है
और जो एक घटिया दोहराव के
क्रम में खो जाती है
सबसे ख़तरनाक वो गीत होता है
जो मरसिए की तरह पढा जाता है
आतंकित लोग़ों के दरवाज़ों पर
गुंडों की तरह अकड़ता है
सबसे ख़तरनाक वो चांद होता है
जो हर हत्याकांड के बाद
वीरान हुए आंगन में चढता है
लेकिन आपकी आंखों में
मिर्चों की तरह नहीं पड़ता
सबसे ख़तरनाक वो दिशा होती है
जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए
और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा
आपके ज़िस्म के पूरब में चुभ जाए

भगत सिंह के बारे में पाश ने लिखा:

उसकी शहादत के बाद बाक़ी लोग
किसी दृश्य की तरह बचे
ताज़ा मुंदी पलकें देश में सिमटती जा रही
झांकी की देश सारा बच रहा बाक़ी
उसके चले जाने के बाद
उसकी शहादत के बाद
अपने भीतर खुलती खिड़की में
लोग़ों की आवाज़ें जम गयीं
उसकी शहादत के बाद
देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोग़ों ने
अपने चेहरे से आंसू नहीं, नाक पोंछी
गला साफ़ कर बोलने की
बोलते ही जाने की मशक की
उससे सम्बन्धित अपनी उस शहादत के बाद
लोग़ों के घरों में, उनके तक़ियों में छिपे हुए
कपड़े की महक की तरह बिखर गया
शहीद होने की घड़ी में वह अकेला था ईश्वर की तरह
लेकिन ईश्वर की तरह वह निस्तेज न था

अब मजमेबाज की सरकार

दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिल गया। सपनों के सौदागर ने सपनों का ऐसा बाजार लगाया कि हर कोई दिल्ली में 'झाड़ू' का खरीददार बन गया। इससे पहले लोकसभा चुनावों में मोदी ने आम जन को सपने बेचे थे और उनके सपनों की बिक्री खूब हुई थी। पर इस बार अरविन्द केजरीवाल जैसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी एनजीओ की दुकान चलाने से ज्यादा ध्यान सपनों की बिक्री पर लगाया था, उनके सपनों की बिक्री खूब हुयी। सपनों की सौदागरी में अरविन्द केजरीवाल ने मोदी को पछाड़ दिया।

एक के खून में व्यापार है (मोदी द्वारा जापान में दिये गये भाषण के अंश से) और दूसरा जाति से व्यापारी है। (केजरीवाल द्वारा दिल्ली चुनाव के दौरान मोदी के आरोप के जावब से) की व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता (सपनों के बेचने की) में जनता छली जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात दंगों के रचयिता ने लोकलुभावन वादों, नारों और झूठी लफ्फ़ाजियों के दम पर देश की जनता को ठगा था। चुनाव जीतने के लिये जाति, धर्म व क्षेत्र की विभाजनकारी राजनीति का सहारा लिया था। इससे भी बढकर कारपोरेट जगत के हीरो बनकर पूरे मीडिया का अपहरण कर लिया गया था। कांग्रेस के मुकाबले अपनी दीनहीन स्थिति का मुजाहिरा करके जनता से सहानुभूति हासिल की गयी थी।

दिल्ली चुनावों में अरविन्द केजरीवाल और उनकी पार्टी ने मोदी की ही पैंतरेबाज़ी अपनायी। अपने को दुखिया के रूप में प्रस्तुत किया, झूठे वादों और झूठी लफ्फ़ाजी का भरपूर सहारा लिया। 'मध्यमवर्ग' के इस 'नायक' ने भी मोदी की ही तरह जाति कार्ड खेला। वे उसी घटिया राजनीति की गिरफ़्त में पाये गये जिसके खिलाफ़ लड़ने का वे वादा कर रहे थे। मसलन उन्होंने धन का चुनाव में न सिर्फ़ बेतहाशा इस्तेमाल किया वरन् चुनाव के दौरान ही उन पर शराब बंटवाने और गलत तरीके से चंदा लेने के भी आरोप लगे। और ऐसे ही आरोप आप ने कांग्रेस और भाजपा पर लगाये।

आद आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावों में मुख्यरूप से कुछ मुद्दों तक खुद को सीमित रखा जिनमें बिजली, पानी और अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का मुद्दा था। लोकपाल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे नहीं थे हालांकि 'आप' स्वयं इन मुद्दों की ही पैदायश है। इस चुनाव में 'आप' के नेताओं ने पूंजीवादी राजनीति के सारे नेताओं के समान मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार किया।

लेकिन केजरीवाल क्या मध्यमवर्गीय जनता व अन्य गरीब गुरबा की समस्याओं का ज़रा भी समाधान प्रस्तुत कर पायेंगे जिन्होंने 'आप' को दो तिहाई से भी ज्यादा बहुमत प्रदान किया है। मान लीजिए पूरे भारत से अलग दिल्ली में लोग़ों के काम सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के होने लगे (जैसे केजरीवाल ने 49 दिनों की अपनी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना) तो क्या होगा? सरकारी बाबुओं के द्वारा लगायी गयी 'टिप्पणी' के परिणामस्वरूप आम जनता को सरकारी कार्यालयों के पहले से कहीं ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे और यदि जनता के काम सरकारी दफ़्तरों में 100 प्रतिशत हो भी जायें तो ज्यादा से ज्यादा जनता को भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ी राहत ही मिल पायेगी।

दूसरी ओर केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा वही कर सकते हैं जो अन्य सुधारवादी पार्टियां व नेता करते रहे हैं। वे ज्यादा से ज्यादा जनता को थोंड़ी राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। हालांकि प्रकारान्तर से ऐसा केरके वे पूंजीपति वर्ग की ही सेवा कर रहे होंगे। ऐसी पार्टियां जनता में न सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर भ्रम पैदा करती हैं वरन् वे जनसंघर्षों व जनअसंतोष पर ठंडा पानी डालने का काम भी करती हैं। वास्तव में 'आप' जैसी पार्टियां व्यवस्था के विरुद्ध फलफूल रहे जनअसंतोष का गर्भपात भी होती हैं। मौजूदा दौर में, उदारीकरण की इस आंधी में अरविन्द केजरीवाल उतना भी नहीं कर पायेंगे जितना कि अन्य सुधारवादी नेताओं वा पार्टियों ने किया है। वैश्विक आर्थिक संकट में इस बात की संभावना और भी कम है कि वे जनता को थोड़ी बहुत भी राहत प्रदान कर सकें। हां, जनता को दिखाने के लिए वे कुछ लोकलुभावन कदम उठा सकते हैं ताकि अपने वोट बैंक को संतुष्ट किया जा सके। क्या अरविन्द केजरीवाल की पार्टी दिल्ली क्षेत्र में जारी आर्थिक नीतियों को लागू होने से रोक सकते हैं? क्या केजरीवाल दिल्ली में जारी ठेकाकरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं? क्या वे अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली, पानी व सड़क की समस्याओं का मुकम्मिल समाधान कर सकते हैं? दिल्ली जैसे राज्य में यह सब कर पाना आसान नहीं है क्योंकि दिल्ली को प्रकारान्तर से केन्द्र की सरकार चलाती है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री एक पुलिसवाले को नहीं हटा सकता तो वह दिल्ली में क़ानून का राज भी कैसे स्थापित कर पायेगा? वह आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कैसे कर सकता है? तब फ़िर अगर वह वादे छल नहीं हैं तो और क्या हैं?

दिल्ली चुनावों में अरविन्द केजरीवाल और उनकी पार्टी ने मोदी की ही पैंतरेबाज़ी अपनायी। अपने को दुखिया के रूप में प्रस्तुत किया, झूठे वादों और झूठी लफ्फ़ाजी का भरपूर सहारा लिया। 'मध्यमवर्ग' के इस 'नायक' ने भी मोदी की ही तरह जाति कार्ड खेला। वे उसी घटिया राजनीति की गिरफ़्त में पाये गये जिसके खिलाफ़ लड़ने का वे वादा कर रहे थे।

जाहिर है केजरीवाल अब विपक्षहीन विधानसभा के नेता होंगे। अब छलिया बनने के बजाय उन्हें दिखाना होगा कि वे वादे पूरे कर सकते हैं। वादे पूरे न होने पर उन्हें उसी जनता के उससे ज़्यादा थप्पड़ खाने को मिल सकते हैं जो उन्हें लोकसभा चुनावों में मिले थे। जनता की आकांक्षाओं को जिस हद तक ये पार्टियां लेकर गयी हैं उसी जनता की खुमारी उतरते देर नहीं लगेगी। अर्श से फर्श तक आने में छः महीनों से ज्यादा का समय नहीं लेगेगा। अगर जन आकांक्षाओं को संबोधित न किया गया तो।

दिल्ली के चुनावों में उन दलों का सूपड़ा पूरी तरह साफ़ हो गया जो सयाम्प्रदायिक राजनीति में सराबोर थे खासकर भाजपा का। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा नेताओं के दंभ को दिल्ली की जनता ने तोड़ दिया। वे अपनी लाज तक न बचा सके इसके बावजूद कि उन्होंनें दिल्ली को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया।

दिल्ली के चुनावों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल व उसकी पार्टी को भारतीय पूंजीपति वर्ग के व्यापक धड़े ने स्वीकार कर लिया है इसके बिना केजरीवाल को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। केजरीवाल की 'माफ़ी सभायें' दरअसल जनता से ज़्यादा पूंजीपति वर्ग के लिये सम्बोधित थीं कि अब वह व्यवस्था के लिए समस्यायें खड़ी करने के बजाय व्यवस्था के हित में काम करेंगे। दरअसल केजरीवाल ने अपना चरित्र तो उसी दिन साफ़ कर दिया था जब अण्णा आन्दोलन के दौरान दिये गये साक्षात्कार में एंकर ने पूछा था कि आपका विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में है या नहीं और तब केजरीवाल ने 'हां' में जवाब दिया था। इस प्रकार अरविन्द केजरीवाल की ''क्रांति'' के पूरा होने के दिन शुरू हो गये। आने वाले दिनों में लोग अरविन्द व आप की ''क्रांति'' देखेंगे और मजमेबान की इस ''क्रांति'' पर इस देश की जनता ''मुस्करायेगी''।

-नागरिक

हाशिमपुरा के असली कातिल!

पेज एक का शेष

था कि बहुत से जनवादी संगठनों और न्याय प्रिय वकीलों ने इसे दफ़न नहीं होने दिया। दरअसल अगर गाज़ियाबाद पुलिस ने उस रात ये दोनों मुकदमें दर्ज करने की हिम्मत न दिखाई होती तो पी ए सी की योजना लाशों को नहर में बहा कर सब कुछ भूल जाने की थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की सशस्त्र सेना यानी पी ए सी का चरित्र हमेशा से घोर साम्प्रदायिक रहा है। उन पर लगातार साम्प्रदायिक दंगों में मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता आया है। यहां तक कि 1974 तक, जब हेमवतीनंदन बहुगुणा यू पी के मुख्यमंत्री बने, पी ए सी में एक भी मुसलमान सिपाही या अधिकारी भर्ती नहीं किया जाता था। यू पी पुलिस में झूठी पुलिस मुठभेड़ों का रिवाज पुराना है। पुलिस हिरासत में अपराधी दिखा कर मार देना उनके लिये आम बात है। साम्प्रदायिक दंगों के दौरान 'बदमाशों' को मार कर नदी नहर में चलता कर देना भी कोई नई प्रथा नहीं है। हाशिमपुरा में बस इतना हुआ कि शीर्ष राजनीतिक संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में डंके की चोट पर हत्यायें की गयीं।

हत्यारों को बरी किये जाने से न्याय व्यवस्था की ऐसी भद्द पिटी है कि दोबारा नये सिरे से तफ़्तीश करने की मांग भी ज़ोर पकड़ रही है। यदि ऐसा हुआ तो आंच राजनीतिक किरदारों तक भी पहुंचेगी।

मज़दूर मोर्चा

नियमित रूप से हर माह की पहली व सोलह तारीख को प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से संपर्क करें। कोई दिक्कत होने पर फ़रीदाबाद के पाठक शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर तथा बल्लभगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज़ एजेन्सी फोन नं 9811477204, करनाल के पाठक अशोक कुमार जैन, फुटवियर जवाहर मार्किट सदर बाजार से फोन नं 9896436739 पर सम्पर्क करें।

फरीदाबाद में अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीनल सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207